Demand for allocation of funds under the 'Khelo India Scheme' in proportion to the players' participation in International tournaments from respective States

SHRI VIKRAMJIT SINGH SAHNEY (PUNJAB): Mr. Deputy Chairman, Sir, first of all, I would like to congratulate Sarabjot Singh and Manu Bhaker, two athletes from Punjab and Haryana, for bringing laurels to the country by winning two medals in shooting for India in the Paris Olympics, 2024.

Sir, I stand in this august House to bring to your kind attention a matter of significant concern, regarding judicious allocation under the *Khelo India* Scheme. As we celebrate the achievements and potential of our athletes on the global stage, it is crucial to address the disparities that could undermine our efforts in nurturing and promoting sports excellence. In the ongoing Paris Olympics, States like Punjab, for example, have demonstrated remarkable prowess and commitment. Out of the 117-strong national contingent that was sent to Paris, Punjab has contributed 19 athletes and Haryana has contributed 24, which represents about 20 per cent each of our Olympic participants. This achievement underscores these States' dedication to sports and its capacity to produce top-tier talent. However, you will be astonished to note that there is concerning imbalance when we examine the allocation of funds under *Khelo India* Scheme. Punjab has been allocated a meager sum of just Rs. 78 crore, which is 3.5 per cent of the allocation. कहाँ वे 117 में 20 और 24 एथलीट्स भेज रहे हैं। पंजाब, हरियाणा को 78 या 60 करोड़ मिला। कई स्टेट्स को 428 करोड़ मिले हैं। जिनको 428 करोड़ मिले हैं, साहब, उन्होंने दो एथलीट्स भेजे हैं। शायद खेल मंत्री जी हैं, जो हो गया सो हो गया, अब आप इस पर आज ही सुधार कीजिए। मेरिट भी कोई चीज़ है, डेमोक्रेसी है, किसी निज़ाम से चलिए। जो स्टेट ज्यादा कॉन्टिंजेंट भेजती है, जो स्टेट ज्यादा मेडल जीतती है, उनको *pro-rata* पर फंड्स एलोकेट होने चाहिए। Hon. Finance Minister is also here. She is musing it. I think fair and equitable distribution होना चाहिए। Adequate funding is essential for our athletes, क्योंकि हमारा जो यूथ है, demographic dividend है, we must engage our youth in pursuits like sports, to keep them fit and not to let them fall prey to any vices like drugs. तभी हम कह सकेंगे - चक दे इंडिया। जय हिंद!

श्री उपसभापति: धन्यवाद, माननीय विक्रमजीत सिंह जी।

The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Vikramjit Singh Sahney: Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu), Shrimati Phulo Devi Netam (Chhattisgarh), Shri M. Shanmugam (Tamil Nadu), Shri Saket Gokhale (West Bengal), Shrimati Mahua Maji (Jharkhand), Shri Niranjan Bishi

(Odisha), Ms. Dola Sen (West Bengal), Shri A.A. Rahim (Kerala), Shri Haris Beeran (Kerala), Dr. John Brittas (Kerala), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Jawhar Sircar (West Bengal), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shrimati Sulata Deo, (Odisha) and Shri Sant Balbir Singh (Punjab).

Depletion of water bodies and ponds in the country due to illegal encroachment and construction

श्रीमती संगीता यादव (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति जी, आपने मुझे तालाब के संरक्षण के अवसर पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूं और आपके माध्यम से सदन को प्रणाम करती हूं। आज मैं इस सदन के माध्यम से आप सभी लोगों का ध्यान एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। हम सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है, लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है? आज गांव और तहसील पर तालाबों को पाटकर घर बनाए जा रहे हैं। यह प्रक्रिया पूरे देश में जारी है। तालाबों पर लगातार कब्जा होने से न केवल मानव, बल्कि जीव-जंतु और हमारे पर्यावरण को भी बहुत ही हानि पहुंच रही है। वर्षा का जल तालाब में इकट्ठा होना था, लेकिन अब तालाबों के अभाव में जल भराव की समस्या जगह-जगह हो रही है। तालाबों पर कब्जा करने में भूमाफिया भी शामिल है, हालांकि केंद्र और राज्य सरकारों ने समय-समय पर इसमें कई कठोर नियम बनाए हैं। इसके बावजूद भी तालाबों पर अवैध कब्जा लगातार जारी है। जल शक्ति मंत्रालय के डेटा के मुताबिक देश में मौजूद वाटर बॉडीज़ में सबसे ज्यादा हमारे तालाब हैं, जिनका हिस्सा करीब 59.5 फीसदी है, यानी आधे से ज्यादा हैं। तालाब पहले भी पानी का एक बहुत बड़ा स्रोत था और आज भी बना हुआ है, जिसकी अनदेखी हो रही है। मैं एक मीडिया की खबर भी यहां पर बताना चाहूंगी। नोएडा में 211 तालाब थे, जिनमें भूमाफियाओं ने कब्जा किया है। 24 अप्रैल, 2024 की एक मीडिया खबर में यह बताया गया है कि देश में लगभग 2.5 लाख तालाब गायब हो चुके हैं।

उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्रीय और राज्य दोनों सरकारों से निवेदन करना चाहती हूं कि हर तहसील में तालाबों की सूची बनाकर उनकी जांच कराई जाए और उस सूची को आम जन के लिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाए। जब मैं चौरी-चौरा में विधायक थी, तब मैंने इस पर काम भी किया था और यह काफी सफल भी रहा था। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करना चाहूंगी कि भूमाफियाओं पर सख्त नियम बनाकर उन पर कार्रवाई की जाए और जल संरक्षण कर, देश को पर्यावरणीय संकट से बचाया जाए।

श्री उपसभापति: धन्यवाद, माननीया संगीता यादव।

The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shrimati Sangeeta Yadav: Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu), Shri Saket Gokhale (West Bengal), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri Devendra